दैनिक जागरण
जीवन में महत्वपूर्ण सिर्फ इरादा होता है

मोदी के मंत्री

मोदी सरकार की वापसी के बाद जिज्ञासा केवल यही नहीं थी कि इस बार किसे मंत्रिपरिषद में जगह मिलती है, बल्कि यह भी थी कि किसे कौन सा मंत्रालय मिलता है? इन दोनों सवालों का जवाब सामने आ गया है और सरकार में शामिल हुए भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने जहां गृहमंत्री की जिम्मेदारी संभाली वहीं निर्मला सीतारमण ने वित्त मंत्रालय की। अमित शाह ने भाजपा अध्यक्ष के तौर पर जो कुछ हासिल किया वह एक मिसाल है। अब उनसे यही उम्मीद की जाती है कि गृहमंत्री के रूप में भी वह विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हुए मिसाल कायम करेंगे। निर्मला सीतारमण रक्षा मंत्री बनने वाली पहली महिला थीं। अब वह वित्त मंत्रालय संभालने वाली पहली महिला भी बन गई हैं। चूंकि वह आर्थिक मामलों की अच्छी जानकार हैं इसलिए वित्त मंत्री के रूप में उनका चयन उपयुक्त फैसला है। ऐसा ही फैसला विदेश सचिव रहे एस जयशंकर को विदेश मंत्री बनाने का भी है। उनके शपथ लेते ही जहां यह स्पष्ट हो गया था कि वह अगले विदेश मंत्री बनने जा रहे हैं वहीं यह भी कि प्रधानमंत्री विदेश नीति को पहले जैसा ही महत्व देने वाले हैं। राजदूत के तौर पर अमेरिका और चीन में काम कर चुके जयशंकर सुषमा स्वराज की जगह लेंगे जिन्होंने एक छाप छोड़ी है। यह छाप इतनी गहरी है कि विदेश मंत्रालय ही नहीं, देश भी उनकी कमी महसूस करेगा। उन्हें इसके लिए जाना जाएगा कि उन्होंने अपने नेतृत्व में विदेश मंत्रालय को आम आदमी से जोड़ा। मंत्रिपरिषद को सुषमा स्वराज की तरह ही अरुण जेटली की भी कमी महसूस होगी, जिन्होंने सेहत के चलते सरकार से दूर रहने का फैसला लिया। उन्होंने नोटबंदी के साथ ही देश के कर ढांचे की तस्वीर बदलने वाले जीएसटी को ही लागू नहीं कराया, बल्कि हर मुश्किल वक्त पार्टी और सरकार के लिए ढाल भी बने।

मंत्रियों के चयन और विभागों के बंटवारे से यह साफ है कि प्रधानमंत्री ने एक ओर जहां नेताओं की क्षमता को महत्व दिया है वहीं निरतंरता का भी ध्यान रखा और शायद इसीलिए आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों से भली तरह परिचित राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसी तरह बेहतर काम कर दिखाने वाले नितिन गडकरी के पास परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय तो है ही, उन्हें सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय की भी जिम्मेदारी दी गई है। इसके प्रति सुनिश्चित हुआ जा सकता है कि वह इन उद्योगों की समस्याओं का समाधान करने में सक्षम होंगे। चूंकि उनके कुशल प्रशासक होने में किसी को संदेह नहीं इसलिए एक बार फिर उनसे बेहतर नतीजे देने की उम्मीद की जाती है। ऐसी ही उम्मीद अन्य मंत्रियों से भी की जाती है-इसलिए और भी, क्योंकि मोदी सरकार से लोगों की अपेक्षाएं और बढ़ गई हैं। अनुभवी नेताओं को महत्वपूर्ण मंत्रालय दिए जाने और नए चेहरों को मंत्री बनाए जाने से मंत्रिपरिषद को जरूरी ऊर्जा और गति मिलनी चाहिए। नए मंत्रियों की क्षमता का आकलन तो उनके कामकाज से ही होगा, लेकिन यह उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री ने उन्हें मंत्रिपरिषद में स्थान देकर यह संदेश भी दिया कि भाजपा नए और काबिल लोगों को मौके देने वाली पार्टी है।

जय श्रीराम और ममता

लोकसभा चुनाव समाप्त हो चुका है, पर बंगाल में ऐसा लग रहा है कि चुनाव जारी है और तृणमूल प्रमुख एवं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब भी चुनावी मोड में हैं। चार मई को पश्चिम मेदिनीपुर जिले के चंद्रकोणा में जब ममता का काफिला गुजर रहा था तो कुछ लोगों ने जय श्रीराम के नारे लगा दिए। फिर क्या था ममता ने काफिला रुकवा कर नारा लगाने वालों को भला-बुरा कहा ही साथ ही कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हो गई थी। हालांकि पुलिस ने गिरफ्तारी से इन्कार किया था। इसे लेकर ममता की देशभर में काफी आलोचना हुई थी। इस मुद्दे को लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने जमकर उछाला था। लगा कि अब इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होगी, परंतु गुरुवार को जिस तरह से ममता ने उत्तर 24 परगना जिले के भाटपाड़ा विधानसभा क्षेत्र में जय श्रीराम के नारे लगाने के बाद रिएक्ट किया है उस मुद्दे को फिर से हवा मिल गई है।

जय श्रीराम का नारा लगाने वालों को गुरुवार को गाड़ी से उतरकर मुख्यमंत्री ने अपराधी कहते हुए चमड़ा खींच लेने की धमकी दी थी। मुख्यमंत्री की धमकी के बावजूद लोग डरे नहीं और जय श्रीराम का नारा लगाते रहे। ममता का काफिला गुजरने के बाद पुलिस हरकत में आई और नारेबाजी का वीडियो देखकर लोगों की पहचान करने के बाद रात में दबिश दे दी। पकड़ने के बावजूद पुलिस उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं दिखा रही है। पुलिस अधिकारी असमंजस में हैं कि जय श्रीराम बोलने पर कौन सी धारा लगेगी, परंतु यहां सवाल यह उठ रहा है कि आखिर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जय श्रीराम के नारे से इतनी चिढ़ क्यों रही हैं? उन्होंने जिस तरह से जय श्रीराम बोलने वालों के खिलाफ प्रतिक्रिया देती दिख रही हैं उससे लोग भी अवाक हैं। जय श्रीराम को कभी गाली बोल रही हैं तो कभी बोलने वाले को अपराधी बता रही हैं। यह दूसरी बार ऐसी घटना हुई है। क्या एक सीएम को इस तरह सरेआम सड़क पर लोगों को धमकी देना सही है? इस पर उन्हें सोचने की जरूरत है।

प्रचंड जनादेश के संदेश

डॉ. विजय राणा

मोदी के लिए यह सिंगापुर की कायापलट करने वाले ली-क्वान-यू पड़ाव है, अब उन्हें भी भारतीय लोकतंत्र को योग्यतंत्र में बदलना होगा

वर्ष 2019 के जनादेश से हमें दो संदेश मिलते हैं। एक तो यह कि तमाम विविधताओं के बावजूद जब भारत के नागरिकों के सामने अपने भविष्य की दिशा तय करने की चुनौती आती है तो वे एक राष्ट्रीय सहमति का निर्माण करने में सक्षम होते हैं। हम बुद्धिजीवी और पत्रकार दिशाभ्रम के शिकार हो सकते हैं, लेकिन जनता इस समस्या से पीड़ित नहीं है। जनादेश से जुड़ा दूसरा संदेश यह है कि मिथ्या प्रचार करने वाले सबसे पहले खुद अपने विचारों में कैद होकर बाहरी दुनिया से बेखबर हो जाते हैं। गुजरात से लेकर असम तक और कर्नाटक से लेकर हिमाचल तक मतदाताओं ने एकमत से देश की बागडोर प्रधानमंत्री मोदी को सौंपने का फैसला किया। यह राष्ट्रीय सहमति हमारे लोकतंत्र की परिपक्वता का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को विपक्ष कभी प्रभावी चुनौती नहीं दे पाया, लेकिन किसी सकारात्मक कार्यक्रम के आधार पर भारी बहुमत हासिल करने का एक उदाहरण पहले भी मिला था। 1971 में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ जैसे नारे के दम पर सत्ता हासिल की थी। हालांकि वह इस वादे को निभाने में बुरी तरह विफल रही थीं। 1984 में राजीव गांधी को भारी बहुमत मिला था, लेकिन वह जनादेश इंदिरा गांधी की हत्या से उपजी सहानुभूति का परिणाम था।

पीवी नरसिंह राव, अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह की गठबंधन सरकारें अपने अस्तित्व को बचाने और रूठे सहयोगियों को मनाने में ही लगी रहीं। हालांकि इस दौरान कुछ बहुत अच्छे काम भी हुए, लेकिन मनमोहन सिंह के शब्दों में 'गठबंधन की राजनीति' की मजबूरियों के कारण ये सरकारें सांसदों की खरीद फरोख्त, भ्रष्टाचार में लिप्त मंत्रियों के बचाव और देश की अर्थनीति और विदेश नीति से संबंधित कठोर फैसलों से कतराती रहीं।

लोकसभा चुनाव के दौरान कई बुद्धिजीवी तानाशाही का भय दिखाकर कमजोर सरकार और मजबूत विपक्ष की दुहाई देते रहे, लेकिन यह जनता है और वह सब जानती है। गठबंधन की कमजोर सरकारें वोटबैंक की राजनीति की गुलाम रही हैं। समाज के कुछ तबके उनकी बांह मरोड़ते रहे। वे देशहित में सख्त और दूरगामी कदम नहीं उठा सकी थीं। कल्पना कीजिए कि यदि मोदी किसी गठबंधन सरकार के प्रधानमंत्री होते तो क्या वह टैक्स-चोरी पर आधारित काले धन वाली अर्थव्यवस्था पर कुठाराघात करने वाला जीएसटी कानून लागू कर सकते थे या फिर पाकिस्तान के खिलाफ पहले सर्जिकल और फिर एयर स्ट्राइक कर सकते थे? जनता ने बड़ी अपेक्षाओं के साथ मोदी को ताकत दी है। राजनीतिक सहमति जनता ने बनाई है, लेकिन अब सामाजिक सहमति का निर्माण मोदी को करना होगा। मोदी को वर्ग हित, जाति हित और संप्रदाय हित की राजनीति से ऊपर उठकर बिना किसी भेदभाव के देश के सभी नागरिकों के लिए काम करना होगा और इस क्रम में एक शांत, सक्रिय और श्रमशील समाज का निर्माण करना होगा। अड़ंगेबाज अफसरशाही को जवाबदेही सिखानी होगी और नकारा अधिकारियों को बाहर का दरवाजा दिखाना होगा। अपने बड़बोलेपन से सरकार की प्रतिष्ठा को धूमिल करने वाले नेताओं पर नकेल कसनी होगी। उन्हें सुस्त पड़ी आर्थिक वृद्धि को गति देनी होगी। रोजगार के अवसर बढ़ाने होंगे। किसान को खेती के साथ, कृषि उत्पाद के बेहतर संरक्षण और प्रसंस्करण की सस्ती तकनीक उपलब्ध करानी होगी।

अवधेश राजपूत

मोदी के लिए यह ली-क्वान-यू पड़ाव है। ली सिंगापुर के ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने देश की कायापलट कर दी। अब मोदी को लोकतंत्र को योग्यतंत्र में बदलना होगा। उन्हें एक ऐसे समाज का निर्माण करना होगा जहां मेहनत की इज्जत हो, जहां ज्ञान को सम्मान मिले और योग्य व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के आगे बढ़ने के अवसर मिलें। रेलवे प्लेटफॉर्म से रायसीना हिल तक का जो सफर उन्होंने तय किया है, ऐसे सफर के मौके सभी सुयोग्य और प्रतिभावान लोगों को मिलने चाहिए। इसके लिए उन्हें आलस्य, अज्ञान और अक्षमता की जनक अभिजात्य मनोवृत्ति से लड़ना होगा। यह एक ऐसी सामाजिक बीमारी है जिसमें एक छोटा सा वर्ग देश के संसाधनों और प्रगति के अवसरों को हथिया कर बैठ जाता है और बाकी बचे लोगों की प्रगति के मार्ग में अड़ंगे लगाकर उन्हें गरीबी और अशिक्षा के दुष्चक्र में फंसे रहने का षड्यंत्र रचता है। यह अभिजात्य वर्ग वातानुकूलित सभागारों और पांचसितारा होटलों में आयोजित सेमिनारों में गरीबों और पिछड़ों के नाम पर पर्चे पढ़ता है और वोटबैंक की राजनीति को नैतिक संरक्षण देता है। उसका असल उद्देश्य होता है अपने हितों का संरक्षण और गरीब को गरीब बनाए रखना। दूसरी बात यह कि प्रचार भले ही किसी वस्तु या विचार का हो, प्रचारकर्ता ही सबसे पहले उस विचार का शिकार होता है। मोदी विरोधी प्रचार में जुटे नेताओं से लेकर वामपंथी विचारक तक सबको यह विश्वास हो चला था कि 'चौकीदार चोर है' जबकि इस आरोप को सिद्ध करने के लिए वे और खुद राहुल गांधी कोई विश्वसनीय प्रमाण नहीं दे सके। कुछ जाने-माने मोदी विरोधी पत्रकारों और वकीलों ने आधे अधूरे सरकारी दस्तावेजों की मदद से मोदी को 'चोर' सिद्ध करने के भरपूर प्रयास जरूर किए, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय से लेकर जनता की चुनाव रूपी अदालत ने इन आरोपों को खारिज कर दिया।

चुनाव के दौरान देशव्यापी जनअसंतोष को लेकर भी दुष्प्रचार किया गया। मसलन युवा बेरोजगार है, किसान नाराज है, अल्पसंख्यक असुरक्षित हैं, दलित हिंसा के शिकार हैं, व्यापारी टैक्स-आतंकवाद से व्यथित हैं यानी समाज के हर तबके को मोदी ने धोखा दिया है। दिल्ली के स्वनिर्मित वैचारिक बुलबुले मे रहने वाले ये लोग जब चुनावी भ्रमण के लिए निकले तो उनकी चुनावी रिपोर्ट जनता की नब्ज नहीं पकड़ पाई। वे अपने ही प्रचार के शिकार बन गए। मिसाल के तौर पर, गांव में सिर पर भूसा ढोने वाली 11 वर्षीय एक किशोरी की मेहनत में हमारे अंग्रेजीदां पत्रकारों को शोषण दिखाई दिया। यह किशोरी नए भारत कि बेटी है, जिसे मेहनत करने में शर्म नहीं आती। उसके सपने जिंदा हैं। वह डॉक्टर बनना चाहती है। उसके सपनों को पूरा करने के लिए, कम आय के बावजूद, उसके पिता उसे प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। उसके पास पक्का मकान है। शौचालय भी है और मोदी सरकार ने उसे गैस सिलेंडर भी दिया है, लेकिन चुनावी पर्यटन पर निकले पत्रकार महोदय इस किशोरी की जिंदगी पर तरस खाते हुए उसे गरीबी और शोषण के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते रहे। सच तो यह है कि यह किशोरी नए भारत में होने वाले अभूतपूर्व आर्थिक समावेशीकरण का एक नायाब उदाहरण है, लेकिन यह बात अंग्रेजियत के खंडहरों में आलीशान जिंदगी बिताने वाले दिल्ली के पत्रकारों की समझ से बाहर है। वे यह नहीं देख सके कि गांव और कस्बों में रहने वाले भारत में करोड़ों किशोर और युवा बेहतर जिंदगी का सपना देखने लगे हैं। इसी कारण जब देश की भावी सरकार चुनने का समय आया तो उन्होंने राहुल गांधी की कुंठा और झुंझलाहट को ठुकराकर नरेंद्र मोदी द्वारा दिखाई आशाओं के लोकतंत्र की राह पर चलने का निर्णय लिया।

(बीबीसी हिंदी सेवा के रेडियो संपादक रहे लेखक अनिवासी भारतीय पत्रकार एवं डॉक्यूमेंट्री फिल्मकार हैं)

response@jagran.com

पेयजल संकट से जूझता ग्रामीण भारत

पंकज चतुर्वेदी

ग्रामीण भारत की 85 फीसद आबादी पानी की जरूरतों के लिए जिस भूजल पर निर्भर है उसका स्तर लगातार गिर रहा है

भले ही संविधान के अनुच्छेद 47 में यह दर्ज हो कि प्रत्येक देशवासी को साफ पानी मुहैया करवाना राज्य का दायित्व है, लेकिन आज भी देश की कोई 17 लाख ग्रामीण बसावटों में से लगभग 78 फीसद में ही पानी की न्यूनतम आवश्यक मात्रा पहुंच सकी है। यह भी विडंबना है कि इस पर अब तक करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद सरकार परियोजना के लाभों को प्राप्त करने में विफल रही है। आज महज 45,053 गांवों को नल-जल और हैंडपंपों की सुविधा मिली है, लेकिन लगभग 19,000 गांव ऐसे भी हैं जहां साफ पीने के पानी का कोई नियमित साधन नहीं है। हजारों बस्तियां ऐसी हैं जहां लोग कई-कई किलोमीटर पैदल चल कर पानी लाते हैं। ये आंकड़े भारत सरकार के पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के हैं। अगस्त 2018 में सरकार की ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया था कि सरकारी योजनाएं प्रति दिन प्रति व्यक्ति को सुरक्षित पेयजल की दो बाल्टी प्रदान करने में विफल रही हैं, जो कि निर्धारित लक्ष्य का आधा था। रिपोर्ट में कहा गया कि खराब निष्पादन और घटिया प्रबंधन के चलते सारी योजनाएं अपने लक्ष्य से दूर होती गईं।

भारत सरकार ने प्रत्येक ग्रामीण व्यक्ति को पीने, खाना पकाने और अन्य बुनियादी घरेलू जरूरतों के लिए स्थायी आधार पर पानी की न्यूनतम मात्रा उपलब्ध करवाने के इरादे से राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम 2009 में शुरू किया था। इसमें हर घर को परिशोधित जल घर पर ही या सार्वजनिक स्थानों पर नल द्वारा मुहैया करवाने की योजना थी। इसमें 2022 तक देश में शत प्रतिशत शुद्ध पेयजल आपूर्ति का संकल्प था। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट कहती है कि कई हजार करोड़ रुपये खर्च करने के बाद भी यह परियेजना सफेद हाथी साबित हुई है। 2017 तक परियोजना की कुल राशि 89,956 करोड़ रुपये का 90 प्रतिशत हिस्सा खर्च करने के बावजूद यह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में बहुत दूर है। हर जगह यह बात सामने आई कि स्थानीय समाज से सलाह लिए बगैर, स्थानीय पारंपरिक स्रोतों में जल की उपलब्धता पर विचार किए बगैर योजनाएं बनाई गईं। और जब वे पूरी हुईं तो उनका इस्तेमाल ही नहीं हो सका। उदाहरण के लिए पारंपरिक कुओं को असुरक्षित पेयजल स्रोत घोषित कर दिया गया, जबकि महज मामूली साधन व्यय कर इन कुओं को सुरक्षित बनाया जा सकता था। सारी योजना ऊंची टंकी खड़ी करने और पाइप डालने तक सीमित रह गई। यह सोचा ही नहीं गया कि गांव में जब बिजली की आपूर्ति ही नियमित नहीं है तो पानी टंकी में पहुंचेगा कैसे और वितरित कैसे होगा?

गौरतलब है कि हजारों करोड़ रुपये और दसियों योजनाओं के बावजूद आज भी कोई करीब 3.77 करोड़ लोग हर साल दूषित पानी के इस्तेमाल से बीमार पड़ते हैं। लगभग 15 लाख बच्चे दस्त से अकाल मौत मरते हैं। अंदाजा है कि पीने के पानी के कारण बीमार होने वालों से 7.3 करोड़ कार्य दिवस बर्बाद होते हैं। इन सबसे भारतीय अर्थव्यवस्था को हर साल करीब 39 अरब रुपये का नुकसान होता है। ग्रामीण भारत की 85 फीसद आबादी अपनी पानी की जरूरतों के लिए भूजल पर निर्भर है। एक तो भूजल का स्तर लगातार गहराई में जा रहा है, दूसरा भूजल एक ऐसा संसाधन है जो यदि दूषित हो जाए तो उसका निदान बहुत कठिन होता है। गांवों में शौचालय, मल एवं कूड़ा निस्तारण की कोई योजना नहीं होने, खेती में अंधाधुंध रसायनों के इस्तेमाल होने के चलते ग्रामीण भारत को पानी बीमार बना रहा है। करीब 6.6 करोड़ लोग अत्यधिक फ्लोराइड वाले पानी के घातक नतीजों से जूझ रहे हैं तो करीब एक करोड़ लोग अत्यधिक आर्सेनिक वाले पानी के शिकार हैं। कई जगहों पर पानी में लोहे (आयरन) की अधिक मात्रा भी परेशानी का सबब है।

देश में नदी, तालाब, जोहड़, बावड़ी और कई अन्य पारंपरिक जल स्रोत पर्याप्त संख्या में हैं और ये बरसात की हर बूंद को सहेज कर हमारी 2050 तक की जल-मांग को पूरा करने में सक्षम हैं। विडंबना यह है कि नदियां कूड़ा ढोने का मार्ग या रेत निकालने का जरिया बन गई हैं और तालाबों को हमने अपने घर से निकली गंदगी को निबटाने का जरिया बना लिया है। छद्म नल-क्रांति के चलते हम अपने कुओं जैसी पारंपरिक जल व्यवस्था को खुद ही नष्ट कर चुके हैं। आज जरूरत इस बात की है कि सरकार सुरक्षित जल मुहैया करवाने की योजनाओं का पैसा जल संसाधनों को निरापद बनाने, उनके जल ग्रहण क्षेत्र एवं आगम क्षेत्रों को अविरल रखने जैसे कार्य पर व्यय करे। इससे भूजल तंदरुस्त होगा। गांधीजी ने कहा ही था कि प्रकृति इंसान की जरूरतों को तो पूरा कर सकती है, उसके लालच की पूर्ति नहीं कर सकती।

response@jagran.com

तथ्य-कथ्य | प्रचलन में करेंसी नोट (अरब रुपये में)

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

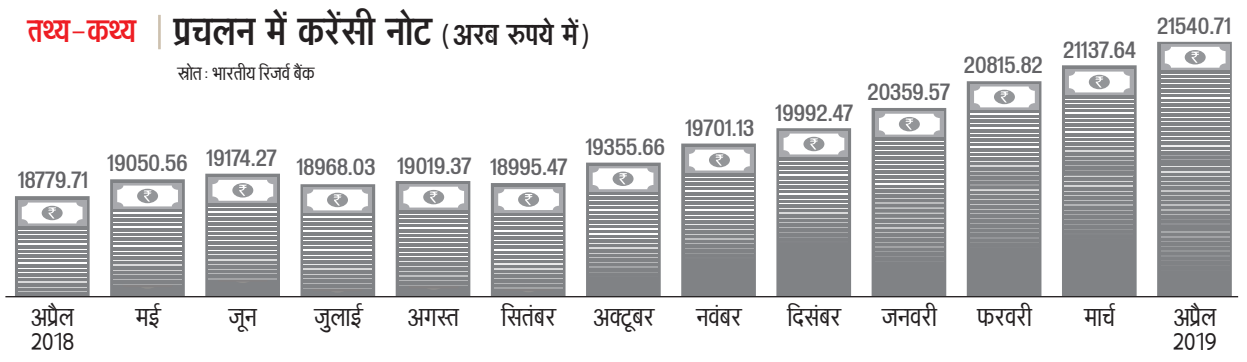

ऊर्जा

ईश्वर की कृपा

इस संसार का प्रत्येक मनुष्य परमात्मा की कृपा दृष्टि प्राप्त करना चाहता है। विशेष रूप से वह जब दुखों के सागर में निमग्न होता है तथा अपने आप को असहाय अनुभव करता है, तब उसका झुकाव परम सत्ता परमात्मा की ओर होता है। ईश्वर की कृपा सब पर अचानक यूं ही नहीं हो जाती। ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए मनुष्य को स्वयं को उचित पात्र बनाना पड़ता है। ईश्वर तो आनंद एवं कृपा का आगाध सागर है, लेकिन उसकी अनुकंपा से वंचित रहने का कारण हमारी अपनी ही विकृतियां होती हैं।

ईश्वर की समीपता का लाभ मनोभूमि को पवित्र बनाए बिना संभव नहीं हो सकता। हमारी दुष्ट तथा तामसिक प्रवृत्तियां प्रभु कृपा प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा हैं। जिस प्रकार धुंधले दर्पण में मुंह दिखाई नहीं पड़ता तथा गंदे पानी की तली में पड़ी हुई वस्तु ओझल रहती है उसी प्रकार अंतःकरण की मलिनता के कारण आत्मा मूर्छित पड़ी रहती है। वासना तथा तृष्णा के आवरण आंखों पर पट्टी बांधे रहते हैं। लोभ तथा अत्यधिक आसक्ति रूपी रस्सी मनुष्य के मानस पटल को इस प्रकार जकड़े रखती है कि उसे प्रभु अनुकंपा प्राप्त हेतु पात्र बनने ही नहीं देती। आत्मिक परिष्कार के बिना प्रभु अनुग्रह प्राप्त होना असंभव है। जप, तप, साधना अंतःकरण पर पड़े मलिन संस्कारों को दूर करने की विधियां हैं।

दुष्ट प्रवृत्तियों से स्थूल शरीर, दुर्बुद्धि से सूक्ष्म शरीर में तामसिक प्रवृत्तियां भर जाती हैं और समूचा व्यक्तित्व पतन के गर्त में जा गिरता है। इसी दुर्गति की दलदल में धंस कर मनुष्य प्रभु कृपा से वंचित रहता है। कठोर चट्टान पर लगातार वर्षा होते हुए भी हरियाली उत्पन्न नहीं होती। इसमें बादलों से अनुरोध करना व्यर्थ है। चट्टान को ही कोमल रेत में बदलना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार मनुष्य को भी अपनी मनोभूमि को पावन बनाना चाहिए। तामसिक तथा कुसंस्कारों की जो परत अंतःकरण पर चढ़ गई है वही आत्मा तथा परमात्मा के साक्षात्कार में सबसे बड़ी बाधक है। मनुष्य विवेकशील प्राणी है। नर से नारायण, पुरुष से पुरुषोत्तम, लघु से महान बनने का एक ही उपाय अंतःकरण की पवित्रता है। शुद्ध अंतःकरण से ही मनुष्य प्रभु के अनुग्रह का पात्र बनता है। ऐसे सात्विक पुरुष को ही प्रभु की अनुकंपा प्राप्त होती है।

आचार्य दीपचंद भारद्वाज

कोई बीमारी नहीं है समलैंगिकता

सुनीता मिश्रा

जैसे हर व्यक्ति का रंग, रूप समान नहीं होता, उसी प्रकार सभी विषमलैंगिक हों यह भी जरूरी नहीं है

हाल ही में देश की महिला धावक दुती चंद ने एक बड़ा खुलासा किया, जिसे सुनने के बाद सभी चौंक गए हैं। दरअसल उन्होंने कहा कि वह समलैंगिक हैं और पिछले कई सालों से इस रिश्ते में रह रही हैं। दरअसल ब्लैकमेलिंग से तंग आकर उन्हें अपने रिश्ते को सार्वजनिक करने के लिए मजबूर होना पड़ा है, क्योंकि उनकी बहन उन्हें ब्लैकमेल कर रही थी। वह इस बात को छिपाने के लिए उनसे 25 लाख रुपये मांग रही थी।

खैर महिला खिलाड़ी ने अपनी बहन की धमकियों से तंग आकर अपने रिश्ते को सार्वजनिक तौर पर कबूल कर लिया है। वह चाहतीं तो पहले ही इस बात को समाज के सामने कबूल सकती थीं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि आज भी हमारा समाज इस रिश्ते को उचित नहीं मानता है। उसके अनुसार समलैंगिक होना एक बीमारी है और ऐसे लोग समाज के लिए खतरा हैं। समलैंगिक वह व्यक्ति होता है जो समान सेक्स या लिंग के प्रति आकर्षित होता है। विषमलैंगिक लोगों से उनकी जीवनशैली अलग होती है। उनकी जेनेटिक संरचना भी भिन्न होती है। समलैंगिकता प्राकृतिक है। जैसे हर व्यक्ति का रंग, रूप समान नहीं होता, उसी प्रकार सभी विषमलैंगिक हों यह भी जरूरी नहीं है।

पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने भारत में समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर करते हुए धारा 377 को मनमाना और अतार्किक बताते हुए असंवैधानिक करार दिया था। कुछ देशों में इन्हें कानूनी मान्यता दे दी गई है, लेकिन आज भी वहां सामाजिक हालात में कोई खास सुधार देखने को नहीं मिलता है। आधुनिक समय में भी ऐसे लोगों को समाज घृणा दृष्टि की से देखता है। फरवरी 2019 में सिनेमाघरों में सोनम कपूर अभिनीत फिल्म 'एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा' रिलीज हुई थी। फिल्म में उन्हें समलैंगिक दिखाया गया था। फिल्में समाज का आईना होती हैं, इसके माध्यम से समलैंगिक लोगों की जीवनशैली, उनके विचार, व्यवहार और समाज की सोच को बखूबी उठाया गया था। एक बात साफ है कि समलैंगिकता कोई बीमारी नहीं है, बल्कि जीवन की एक सच्चाई है। अधिकतर लोगों को लगता है कि समलैंगिकता का बड़ा कारण हार्मोंस में गड़बड़ी होना है, जबकि सच्चाई तो यह है कि इन हार्मोंस का इससे कोई लेना-देना नहीं है।

वास्तव में समाज को ऐसे लोगों को स्वीकारना होगा, नहीं तो हर कोई दुती चंद जैसा बहादुर नहीं है कि वह समाज के तानों का डटकर मुकाबले कर सके। कई लोग तो इसे बताने में भी शर्म महसूस करते हैं और अंत में आत्महत्या जैसा कदम उठा लेते हैं। ऐसे लोगों को भी जीने का अधिकार है। विषमलैंगिक लोगों को समलैंगिक लोगों के अधिकारों के लिए आगे आना होगा। समाज को उनसे छुआछूत का व्यवहार बंद करना होगा। खैर सही मायने में उन्हें इलाज की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें अपनी सोच बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि समलैंगिकता आधुनिक काल का मुद्दा नहीं है। यह मानव सभ्यता के शुरुआती काल से ही अस्तित्व में रहा है।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

तंबाकू पर लगे रोक

सेहत के लिए संकट बने तंबाकू उत्पाद शीर्षक से लिखे अपने आलेख में डॉ. सूर्यकांत ने तंबाकू उत्पादों के सेवन से होने वाली हानियों का उल्लेख किया है। तंबाकू जीवन शक्ति को कम कर देता है और धीरे-धीरे मानव जीवन को लील लेता है। लेखक ने सही लिखा है कि जितना राजस्व कर के रूप में इससे प्राप्त होता है उससे कहीं अधिक राशि तंबाकू जनित बीमारियों के इलाज में लोगों को खर्च करनी पड़ती है। सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू के पैकेटों पर वैधानिक चेतावनी सरकारी हिदायतों के अनुसार बेशक वर्षों से लिखी जा रही है, परंतु इसका असर शून्य ही है। जिसे तंबाकू सेवन की लत पड़ चुकी है, वह इसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहता। देश के लगभग सभी राज्यों में तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ हैं, परंतु इनका कितना असर है सभी को विदित है। हरियाणा की बात की जाए तो वर्षों से राज्य में गुटका, पान मसाला, जर्दा, तंबाकू आदि के उत्पादन, भंडारण एवं वितरण पर पूरी तरह प्रतिबंध है, परंतु हकीकत यह है कि प्रदेश के प्रत्येक गांव, कस्बे एवं शहर में इनकी खुलेआम बिक्री होती है। केवल राजस्व की प्राप्ति के लिए लोगों के जीवन से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। एक विशेष अभियान चलाकर इससे होने वाले दुष्परिणामों के प्रति लोगों को जागरूक करना चाहिए। सरकार और समाजसेवी संस्थाओं को इसके लिए अपनी अग्रणी भूमिका का निर्वहन करना चाहिए।

sureshgoyal8@gmail.com

राष्ट्रवादी विचार की जीत

एक बार फिर मोदी सरकार के नारे के साथ भाजपा ने सरकार बना ली। भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई गैर कांग्रेसी पार्टी लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई हो। प्रियंका गांधी वाड्रा के आने से कांग्रेस के प्रदर्शन में सुधार की उम्मीद जगी थी, परंतु मोदी लहर के सामने किसी की एक न चली। कांग्रेस की हार की एक बड़ी वजह उनके नेताओं के अमर्यादित बयान भी रहे। अभी भले ही कांग्रेस पार्टी के अंदर पद त्याग और इस्तीफे की उठापटक चल रही हो, परंतु उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि शब्द किसी भी चुनाव में बहुत महत्व रखते हैं। किसी स्वच्छ चरित्र वाले व्यक्ति को अपशब्द कहने के बजाय अगर कांग्रेस विकास के मुद्दों पर ध्यान देती तो शायद नतीजे इतने खराब नहीं आते। इसके अतिरिक्त कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के परिणाम से यह मान लिया था कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में उन्हें वोट मिलेंगे ही, जबकि उन्हें मालूम होना चाहिए कि विधानसभा चुनाव से लोकसभा चुनाव के नतीजों का निर्णय नहीं किया जा सकता। इसी तरह गुजरात के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने भाजपा को कड़ी टक्कर दी थी, परंतु लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत सकी। इसका और एक उदाहरण ओडिशा के चुनाव में देखा जा सकता है जहां पर लोकसभा चुनाव में तो भाजपा ने बीजेडी को कड़ी टक्कर दी, परंतु विधानसभा चुनाव में भाजपा बहुत कम सीट ला सकी। बहरहाल लोकसभा चुनाव के परिणाम से यह तो तय हो गया है कि लोगों ने धर्म और जाति की भावनाओं से ऊपर उठकर राष्ट्रवादी विचारधारा को महत्व दिया है जो सराहनीय है।

shubhamgupta.121@gmail.com

आखिर कसूरवार कौन?

गुजरात के एक कोचिंग सेंटर में आग लगने से मारे गए छात्रों का कसूरवार कौन है? आज हर राज्य के कोने-कोने में शिक्षा के नाम पर ऐसी दुकानें खुल रही हैं जिनपर सरकार और प्रशासन का ध्यान ही नहीं जाता है। रोजगार की जद्दोजहद में विद्यार्थी अपना भविष्य संवारने के चक्कर में मजबूरीवश ऐसे संस्थानों में प्रवेश लेते हैं। क्या संबंधित विभागों की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वह ऐसे किसी भी शिक्षा संस्थान की पूर्ण जांच पड़ताल करके ही अनापत्ति प्रमाणपत्र दें। जो शिक्षा संस्थान नियमों की पालना नहीं करते उनको तुरंत बंद कराना चाहिए।

आचार्य राम कुमार बघेल शास्त्री, पलवल

राजनीति के योद्धा

दैनिक जागरण के 31 मई के अंक में प्रदीप सिंह का लेख, चुनावी रणनीति के शहंशाह, मोदी व अमित शाह की कार्यशैली पर बिल्कुल सटीक है। वैसे भी मोदी और अमित शाह की आपसी राजनीतिक समझ, आमजन से जुड़ने की कला, वाक्पटुता और सामरिक विषयों पर उनको महारत हासिल है। यही कारण है कि 5 साल में डंके की चोट पर 16 चुनाव जीते। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में जीत इसकी मिसाल है।

दीपक गौतम, सोनीपत

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व